Vishv UMIYA Foundation | VUF INSTITUTE CIVIL SERVICES

DAILY CURRENT AFFAIRS

IN HINDI

SPECIAL FOR UPSC & GPSC EXAMINATION

DATE : 24-06-25

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Tuesday, 24 June, 2025

Edition : International Table of Contents

Page 01 **Syllabus : GS 2 : International Relations**	ईरान ने कतर और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागीं
Page 06 **Syllabus : GS 2 : Governance**	भारतीय निजी क्षेत्र अभी भी 'विकासशील' अवस्था में है: मंत्री
Page 06 **Syllabus : GS 2 : Indian Polity**	न्यायाधीश परीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के तीन साल के बार अनुभव नियम ने चिंता बढ़ाई
Page 08 **Syllabus : GS 2 : Indian Polity**	चुनाव और प्रक्रियाएँ: चुनाव आयोग पारदर्शिता की दिशा में कुछ सक्रिय कदम उठा रहा है
Page 09 **Syllabus : GS 3 : Indian Economy**	मुद्रास्फीति में गिरावट आई है, लेकिन बेरोजगारी में कमी नहीं
Page 08 : Editorial Analysis: **Syllabus : GS 2 : International Relations**	दक्षिण एशियाई आर्थिक एकीकरण की दयनीय स्थिति

Page 01 : GS 2 : International Relations

पश्चिम एशिया में तनाव के नाटकीय बढ़ाव के तहत, ईरान ने क़तर (अल-उदीद एयर बेस) और इराक (ऐन अल-असद बेस) में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। यह जवाबी कार्रवाई अमेरिका द्वारा ईरानी परमाणु ठिकानों पर किए गए हवाई हमलों के बाद की गई, जिससे क्षेत्र की पहले से ही नाजुक भू-राजनीतिक स्थिति और अधिक बिगड़ गई है।

Iran launches missiles at U.S. bases in Qatar, Iraq

Will never leave violation of 'territorial integrity' unanswered, says Iran after targeting the largest U.S. base in West Asia; Qatar temporarily suspends airspace after U.S. issues advisory for citizens

Stanly Johny
DOHA

Iran launched missile attacks at the al-Udeid Air Base in Qatar, the largest American base in West Asia, on Monday evening in retaliation for the U.S.'s strikes at the Islamic Republic's nuclear facilities on Sunday. Qatar said it "successfully intercepted" the missiles and that there were no deaths and injuries.

The attack came in response to the "blatant military aggression by the criminal regime of the United States" against the nuclear facilities of the Islamic Republic, the Iranian armed forces said in a statement. "Under the directive of the Supreme National Security Council and the command of the Khatam al-Anbiya Central Headquarters, the Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) launched a powerful and devastating missile strike on the al-Udeid base in Qatar," it added. Iran will "never leave any violation of its territorial integrity, sovereignty, or national security unanswered", it said.

Qatar, which lies 190 km south of Iran across the Persian Gulf, houses about 10,000 American soldiers at the base, which also serves as the headquarters of the U.S. Central command.

Iran also targeted the Ain al-Assad base housing U.S. troops in western Iraq, an Iraqi security official told *The Associated Press*.

On Monday evening, Qatar's Foreign Ministry announced the temporary suspension of airspace, "aimed at ensuring safety of residents and visitors", following an advisory from the U.S. Embassy in Doha asking American citizens to move to shelters.

By 7.40 p.m., several rounds of loud explosions were heard in central Doha, with multiple projectiles stopped by interceptors illuminating the night sky. The attack lasted a few minutes, and public life in Doha remained largely unaffected.

'Airspace safe'

Qatar's Defence Ministry said its air defences "successfully intercepted" Iran's missile attack. "The incident did not result in any deaths or injuries," the Ministry said in a statement. The Ministry reiterated that the "airspace and territory of the state of Qatar are safe and that the Qatar Armed Forces are always ready to deal with any threat."

Earlier in the day, Israel carried out a series of strikes hitting government targets in Iran that followed a salvo of missiles and drones fired by Tehran at Israel.

Qatar's Foreign Ministry "strongly condemned" the Iran attack. "We consider this a flagrant violation of the sovereignty of the State of Qatar, its airspace, international law, and the United Nations Charter," Foreign Ministry spokesperson Majed Al Ansari said in a statement. "We affirm that Qatar reserves the right to respond directly in a manner equivalent with the nature and scale of this brazen aggression, in line with international law."

Just before the attacks, Iranian President Masoud Pezeshkian wrote on X: "We neither initiated the war nor seeking it. But we will not leave invasion to the great Iran without answer." Iran said earlier on Monday that its missiles targeted Israeli cities of Haifa and Tel Aviv, according to Iranian state television.

U.S. President Donald Trump remained quiet on Iran's missile attacks.

The Indian mission in Doha urged the Indian community "to be cautious and remain indoors".

The attack came after a meeting between Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi and Russian President Vladimir Putin in Moscow. Mr. Araghchi described Iran-Russia ties as "very close and historic" , and emphasised Iran's close coordination with Russia on regional and nuclear issues.

In Bahrain, a close neighbour of Qatar that hosts the U.S. Fifth Fleet, the American Embassy "temporarily shifted a portion of its employees to local telework", it said on X. On Monday, Bahrain suspended air traffic temporarily after the Iran attack.

RELATED REPORTS
» PAGE 5, 14 & 15

Doubling down

Iranian armed forces said that the attack came in response to the 'blatant military aggression by the criminal regime of the United States'

- Qatar's al-Udeid Air Base houses about 10,000 American soldiers, and also serves as the headquarters of the U.S. Central command
- Iran strikes also target Ain al-Assad base housing U.S. troops in western Iraq

New front: Projectiles seen in the sky over Doha, Qatar, after Iran's armed forces targeted U.S. al-Udeid base on Monday night. REUTERS

मुख्य घटनाक्रम:

- **ईरान की प्रतिक्रिया:** अपनी सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के निर्देश पर, ईरान की आईआरजीसी (IRGC) ने एक "विनाशकारी" मिसाइल हमला किया और अमेरिका की कार्रवाई को "साफ़ तौर पर सैन्य आक्रामकता" बताया। ईरान ने कहा कि वह अपनी संप्रभुता के उल्लंघन को कभी अनुत्तरित नहीं छोड़ेगा।
- **लक्षित ठिकाने:**
  - **अल-उदीद एयर बेस (क़तर):** यह बेस 10,000 से अधिक अमेरिकी सैनिकों और अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुख्यालय का स्थान है।
  - **ऐन अल-असद बेस (इराक):** यह बेस पहले भी कई बार लक्षित किया जा चुका है, खासकर 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद।
- **क़तर की प्रतिक्रिया:** क़तर ने सभी आने वाली मिसाइलों को रोक लिया और कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन उसने ईरानी कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की और इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया। उसने अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत समानुपाती जवाब देने की बात कही और एहतियातन अपने हवाई क्षेत्र को अस्थायी रूप से बंद कर दिया।
- **जनता और कूटनीतिक प्रभाव:**
  - दोहा में विस्फोटों की आवाज़ सुनी गई, लेकिन सामान्य जीवन स्थिर बना रहा।
  - दोहा स्थित भारतीय मिशन ने भारतीय नागरिकों को घरों के भीतर रहने की सलाह दी।
  - बहरीन ने हवाई यातायात को स्थगित कर दिया और अपने दूतावास के स्टाफ को दूरस्थ कार्य पर भेजा।
- **वैश्विक प्रतिक्रियाएँ:**
  - ईरान ने रूस के साथ समन्वय किया, जिससे क्षेत्रीय गठबंधन के पुनर्गठन के संकेत मिलते हैं।
  - अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, जो संभावित रूप से सतर्क या रणनीतिक सोच को दर्शाता है।

अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाव:

1. **पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव:**
   o ईरान-अमेरिका के बीच प्रत्यक्ष सैन्य टकराव सामने आ रहा है।
   o क़तर, जो आमतौर पर एक राजनयिक मध्यस्थ की भूमिका में रहता है, अब सैन्य रूप से प्रभावित हो गया है।
2. **संप्रभुता बनाम सुरक्षा की दुविधा:**
   o ईरान ने आत्म-रक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांत का हवाला दिया, जबकि क़तर ने संप्रभुता और गैर-आक्रामकता पर ज़ोर दिया।
   o इससे अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत पूर्व-खतरनाक और जवाबी हमलों की वैधता पर सवाल उठते हैं।
3. **क्षेत्रीय समीकरणों में बदलाव:**
   o ईरान का रूस के साथ समन्वय पश्चिम एशिया में गुट निर्माण की ओर इशारा करता है।

o पहले से ही शामिल और लक्षित इज़राइल के साथ, यह संघर्ष कई क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियों को अपनी चपेट में ले सकता है।

4. **भारत पर प्रभाव:**
   o क़तर, बहरीन और यूएई में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा एक चिंता का विषय बनती जा रही है।
   o फारस की खाड़ी में अस्थिरता के कारण ऊर्जा आपूर्ति में बाधा या तेल की कीमतों में वृद्धि हो सकती है।
   o अमेरिका, ईरान, इज़राइल और खाड़ी देशों के साथ भारत के संतुलित संबंधों को बनाए रखना अब और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है।

5. **वैश्विक शांति और कूटनीति:**
   o संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर हस्तक्षेप का दबाव बढ़ सकता है।
   o यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध शक्तियों और कूटनीतिक प्रयासों पर चर्चाओं की संभावना को जन्म देता है।

निष्कर्ष:
मिसाइल हमले पश्चिम एशिया की भू-राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाते हैं, जिनके क्षेत्रीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक कूटनीति पर दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। भारत के लिए, एक संतुलित राजनयिक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जिसमें राष्ट्रीय हितों की रक्षा, विदेशों में नागरिकों की सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों के माध्यम से शांति की वकालत शामिल होनी चाहिए।

UPSC Mains Practice Question

Ques : "पश्चिम एशिया रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और नाजुक कूटनीति का रंगमंच बना हुआ है।" हाल ही में ईरान-अमेरिका टकराव और कतर और इराक में मिसाइल हमलों के मद्देनजर, क्षेत्र में विकसित हो रही भू-राजनीतिक गतिशीलता का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। **(250 Words)**

Page 01: GS 2 : Governance

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के वैज्ञानिक विभागों की उपलब्धियों को उजागर करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत का निजी क्षेत्र अब भी 'विकासशील चरण' में है, विशेष रूप से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में। यह बयान उस समय आया जब यह सवाल उठे कि भारत के स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (SSLV) के निर्माण में निजी भागीदारी की कमी क्यों है, जबकि सरकार इन क्षेत्रों को उदार बनाने की दिशा में प्रयासरत है।

Indian private sector still in a 'developing' stage: Minister

The space sector has opened up to the private sector only a few years ago, so its capacity building has started only just now; we need a robust, developed private sector, says Jitendra Singh

Jacob Koshy
NEW DELHI

India's private sector is still in a developing stage and will need some time to acquire the "acumen" to make space vehicles or have biotechnology start-ups grow large enough to invite interest from the public markets, Minister for Science, Space and Atomic Energy Jitendra Singh said at a press conference here on Monday.

"We need a robust, developed private sector. There are some gaps... but that's also because past policy has not favoured the robust development of the private sector. It is only after Prime Minister Narendra Modi came that this has started happening. The space sector has opened up to the private sector only four-five years ago and so their capacity building has started only just now. Several projects have been rolled out but we don't have the private sector acumen. This will take time but there is now a shift in the policy," Dr. Singh said.

He was responding to a question on why, despite the government's multiple claims of championing private sector participation in the space sector, no private company was selected to manufacture the Small Satellite Launch Vehicle (SSLV).

Jitendra Singh and Ajay Kumar Sood, Principal Scientific Adviser during a press conference in New Delhi on Monday. R. V. MOORTHY

Many projects have been rolled out but we don't have the private sector acumen, says Minister

Last week, the public sector defence company Hindustan Aeronautics Limited (HAL) bagged a Transfer of Technology (ToT) deal, valued at ₹511 crore, from the Indian Space Research Organisation to build and operate SSLVs.

Bidding for SSLV

The SSLV is a three-stage vehicle to launch satellites that weigh less than 500 kg into the lower earth orbit (LEO). Apart from the HAL, which had applied independently, two other technically qualified bidders were shortlisted: Alpha Design Technologies Ltd. (ADT), Bengaluru, leading a consortium with Agnikul Cosmos and Walchand Industries Ltd.; and Bharat Dynamics Ltd., Hyderabad, leading a consortium with Skyroot Aerospace, Keltron and Bharat Heavy Electricals Ltd. (BHEL). ADT is a subsidiary of the Adani conglomerate. Among the three, the HAL emerged as the highest bidder.

'Sign of success'

Rajesh Gokhale, Secretary, Department of Biotechnology, which oversees the BIRAC (Biotechnology Industry Research Assistance Council) programme that funds biotechnology start-ups since 2012, said that while a start-up listing in the public markets was a sign of success, it was also important to consider market equity.

"The equity of biotechnology start-ups is currently around ₹7,000 crore...they have longer incubation periods," he said in response to a query on when an Indian biotech start-up would hit the public markets.

Dr. Singh was addressing a press conference on the achievements of scientific departments – the Departments of Science and Technology, Biotechnology, Council of Scientific and Industrial Research, and the Ministry of Earth Sciences.

मुख्य बिंदु:

1. **अपर्याप्त निजी क्षेत्र क्षमताएँ:**
   o हालिया उदारीकरण के बावजूद, भारत का निजी क्षेत्र अब तक SSLV जैसे जटिल तकनीकी उत्पादों के स्वतंत्र उत्पादन और संचालन के लिए आवश्यक तकनीकी दक्षता या पैमाना विकसित नहीं कर पाया है।

o डॉ. सिंह ने इस अंतर को ऐतिहासिक नीतिगत सीमाओं का परिणाम बताया, जिन्होंने कोर वैज्ञानिक और रक्षा प्रौद्योगिकियों में निजी क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा नहीं दिया।

2. **अंतरिक्ष क्षेत्र का खुलना:**
   o अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी खिलाड़ियों के लिए औपचारिक रूप से केवल 4–5 वर्ष पहले खोला गया था, जब पीएम मोदी के शासनकाल में IN-SPACe की स्थापना और सुधार लागू किए गए।
   o इस क्षेत्र में क्षमता निर्माण अब भी प्रारंभिक अवस्था में है।

3. **SSLV निर्माण निविदा परिणाम:**
   o निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के दावों के बावजूद, HAL (एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई) ने ₹511 करोड़ का SSLV निर्माण अनुबंध जीत लिया।
   o Agnikul Cosmos, Skyroot Aerospace और Bharat Dynamics Ltd. जैसे निजी कंसोर्टिया तकनीकी रूप से योग्य थे लेकिन व्यावसायिक बोली में पीछे रह गए।

4. **जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की स्थिति:**
   o 2012 से BIRAC के निरंतर समर्थन के बावजूद, अब तक कोई भी भारतीय जैव प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप सार्वजनिक बाजारों में प्रवेश नहीं कर पाया है।
   o इस क्षेत्र का वर्तमान अनुमानित इक्विटी मूल्य लगभग ₹7,000 करोड़ है — जो संभावना को दर्शाता है, परंतु परिपक्वता को नहीं।

नीतिगत और संरचनात्मक प्रभाव:

1. **ऐतिहासिक नीतिगत जड़ता:**
   o भारत के रणनीतिक क्षेत्र (अंतरिक्ष, रक्षा, परमाणु, जैव प्रौद्योगिकी) लंबे समय तक राज्य-प्रभावित रहे, जिससे निजी खिलाड़ी नवाचार और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र से बाहर रहे।

2. **पारिस्थितिकी तंत्र विकास की आवश्यकता:**
   o निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए तकनीकी हस्तांतरण, बाजार पहुंच में आसानी, पूंजी तक पहुंच, और दीर्घकालिक नीतिगत स्थिरता आवश्यक है।
   o सरकारी सुधारों को केवल प्रवेश की अनुमति नहीं, बल्कि मार्गदर्शन और क्षमता संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

3. **संक्रमण में सार्वजनिक उपक्रमों की भूमिका:**
   o HAL जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रभुत्व तब तक बना रह सकता है जब तक निजी क्षेत्र परिपक्व नहीं हो जाता।

4. **वैश्विक प्रतिस्पर्धा और आत्मनिर्भर भारत:**
   o रणनीतिक स्वायत्तता और नवाचार नेतृत्व इस बात पर निर्भर करता है कि निजी खिलाड़ियों को तकनीकी और अनुसंधान श्रृंखला में कैसे जोड़ा जाता है।

निष्कर्ष:
भारत की यह महत्वाकांक्षा कि वह अंतरिक्ष और जैव प्रौद्योगिकी नवाचार का वैश्विक केंद्र बने, केवल उदारीकरण से पूरी नहीं हो सकती, बल्कि इसके लिए संस्थागत समर्थन, अनुसंधान एवं विकास में निवेश, और निजी क्षेत्र में समयबद्ध क्षमता निर्माण आवश्यक है। जहां सरकार की मंशा नीतिगत परिवर्तनों से स्पष्ट है, वहीं अब ज़रूरत इस बात की है कि कार्यान्वयन इस क्षमता अंतर को पाटे और भारतीय निजी कंपनियों को स्टार्टअप से लेकर वैश्विक प्रतिस्पर्धी तकनीकी कंपनियों तक विकसित किया जाए।

UPSC Mains Practice Question

Ques: अंतरिक्ष और जैव प्रौद्योगिकी जैसे उच्च तकनीक क्षेत्रों में भारत के निजी क्षेत्र की क्षमताओं को आकार देने में सरकारी नीति की भूमिका पर चर्चा करें। (250 words)

Page : 06 : GS 2 : Indian Polity

20 मई 2025 को एक महत्वपूर्ण निर्णय में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सेवा की प्रारंभिक स्तर की परीक्षाओं में सम्मिलित होने से पहले बार में तीन वर्षों के अनिवार्य वकालत अनुभव की आवश्यकता को बरकरार रखा। न्यायालय ने इस निर्णय को भावी न्यायाधीशों की व्यावहारिक समझ और तैयारी सुनिश्चित करने के आधार पर उचित ठहराया। हालांकि, इस फैसले ने कानून स्नातकों और अभ्यर्थियों के बीच चिंता पैदा कर दी है, जिनमें से कई इसकी समीक्षा याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दे रहे हैं।

SC's three-year Bar experience rule for judge exam triggers concern

Soibam Rocky Singh
NEW DELHI

The Supreme Court's landmark ruling last month reinstating the requirement that candidates must have at least three years of litigation experience before they can sit for the judicial service examination for entry-level judgeships has prompted concerns over the challenges it may pose for recent graduates.

The court's decision was rooted in the belief that judicial officers must have practical exposure to the courtroom before donning the robe.

"The judges from the very day on which they assume office have to deal with the questions of life, liberty, property and reputation of litigants," the apex court said in the May 20 judgment.

It observed, "Neither knowledge derived from books nor pre-service training can be an adequate substitute for the first-hand experience of the working of the court system and the administration of justice. This is possible only when a candidate is exposed to the atmosphere in the court by assisting the seniors and observing how the lawyers and the judges function in the court." The ruling has triggered concerns among law graduates and aspirants. A review petition filed by Chandrasen Yadav, a young advocate enrolled with the Bar Council of Uttar Pradesh, argues that the mandatory three-year requirement infringes on his fundamental rights.

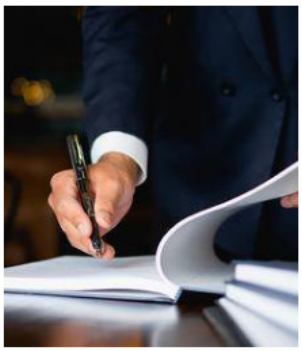

The review petition argues that the court has overlooked key aspects of the very report it cited — the Shetty Commission.

Mr. Yadav submitted that the mandatory three-year practice rule should be implemented only from 2027 to avoid unjust exclusion of recent graduates (2023-2025) who prepared under the previous eligibility criteria.

"Immediate enforcement causes retrospective hardship, violating principles of fairness, legitimate expectation, and equal opportunity under Article 14 of the Constitution," he said.

Another petitioner, Chandra Sharma, who comes from an Army background, highlighted the requirement to obtain a practice certificate from a lawyer with 10 years of standing.

"Lawyers I have worked with had five or seven years of experience. The new norms will make it more difficult for me to get a certificate," she said.

Robust training

The review petition argues that the apex court has overlooked key aspects of the very report it cited – the Shetty Commission. While the 1999 report had recommended a three-year practice period, it also noted that due to practical court training being integrated into modern legal education, such a requirement may not be necessary if robust training is provided post-selection.

मुख्य मुद्दे और घटनाक्रम:

1. **सुप्रीम कोर्ट की तर्कसंगति:**
   o न्यायालय ने यह कहा कि न्यायाधीशों के लिए स्वतंत्रता, संपत्ति और न्याय से संबंधित जटिल मुद्दों से निपटने हेतु व्यावहारिक अदालत अनुभव अत्यंत आवश्यक है।
   o केवल किताबी ज्ञान और सेवा-पूर्व प्रशिक्षण वास्तविक दुनिया के कानूनी अनुभव का विकल्प नहीं हो सकते।
   o न्यायालय ने शेट्टी आयोग (1999) की सिफारिशों का हवाला दिया, जिसने पहली बार इस आवश्यकता का प्रस्ताव दिया था।

2. **अभ्यर्थियों द्वारा उठाई गई चिंताएँ:**
   o **वैध अपेक्षाओं का उल्लंघन:** कई उम्मीदवार (2023 से 2025 के स्नातक) ने पुराने पात्रता मानदंडों के आधार पर तैयारी की थी, जिनमें वकालत अनुभव अनिवार्य नहीं था।
   o **पिछले समय से प्रभाव:** इस नियम की अचानक लागू होने से कोई संक्रमणकालीन राहत दिए बिना बड़ी संख्या में उम्मीदवार बाहर हो जाते हैं।
   o **प्रवेश और समानता से जुड़े मुद्दे:** याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) और अनुच्छेद 19 (पेशे का अधिकार) का उल्लंघन करता है।
   o **व्यावहारिक कठिनाइयाँ:** अभ्यर्थी यह भी कहते हैं कि 10+ वर्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से प्रैक्टिस सर्टिफिकेट प्राप्त करना विशेष रूप से ग्रामीण, आर्थिक रूप से कमजोर या गैर-परंपरागत पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के लिए कठिन है।

3. **शेट्टी आयोग का दृष्टिकोण:**
   o आयोग ने तीन वर्ष के अभ्यास की सिफारिश तो की थी, लेकिन यह भी कहा था कि यदि चयन के बाद ठोस प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, तो यह आवश्यकता अनिवार्य नहीं मानी जा सकती।
   o आधुनिक विधि शिक्षा में पहले से ही मूट कोर्ट, इंटर्नशिप और क्लिनिकल लीगल एजुकेशन शामिल हैं, जो आंशिक रूप से व्यावहारिक अनुभव की आवश्यकता को पूरा करते हैं।

संविधानिक और शासकीय प्रभाव:
• **न्यायपालिका में करियर की पहुंच:** यह निर्णय निम्न न्यायपालिका में प्रवेश की संभावना को सीमित कर सकता है, विशेषकर सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के लिए।
• **न्यायिक स्वतंत्रता बनाम सुलभता:** जहां न्यायिक क्षमता महत्वपूर्ण है, वहीं पात्रता सीमाओं को समावेशिता और विविधता के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।
• **नीति का कार्यान्वयन:** न्यायालय का यह निर्णय अनजाने में पिछले समय से अपात्रता थोप सकता है, जो न्याय और संक्रमणकालीन निष्पक्षता के स्थापित सिद्धांतों को चुनौती देता है।
• **कानूनी शिक्षा पर बहस:** यह प्रश्न भी उठता है कि क्या विधि शिक्षा में सुधार और चयन के बाद का प्रशिक्षण अनिवार्य वकालत अनुभव का विकल्प हो सकते हैं।

निष्कर्ष:
न्यायिक नियुक्तियों में उच्च मानकों को सुनिश्चित करने की सर्वोच्च न्यायालय की मंशा सराहनीय है। हालांकि, तीन वर्ष के बार अनुभव नियम को अचानक लागू करना निष्पक्षता, पहुंच और समावेशिता को लेकर वास्तविक चिंताएँ उत्पन्न करता है। हालिया स्नातकों के लिए चरणबद्ध कार्यान्वयन या संक्रमणकालीन राहत इस बीच न्यायिक दक्षता और संवैधानिक समानता के बीच संतुलन बना सकती है। यह मुद्दा न्यायिक प्रशिक्षण को मज़बूत करने और भविष्य के न्यायाधीशों के लिए विधि शिक्षा की पुनर्कल्पना की तत्काल आवश्यकता को भी उजागर करता है।

UPSC Mains Practice Question

Ques: "न्यायिक क्षमता को समावेशिता और पहुंच के साथ संतुलित किया जाना चाहिए।" न्यायिक सेवा के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए तीन साल का बार अनुभव अनिवार्य करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के मद्देनजर न्यायपालिका तक पहुंच के लिए इसके निहितार्थों की आलोचनात्मक जांच करें। **(250 Words)**

Page 08 : GS 2 : Indian Polity

हाल ही में गुजरात, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल की पाँच विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों ने भारत की क्षेत्रीय राजनीतिक गतिशीलता और चुनावी प्रक्रियाओं में उभरती चुनौतियों को उजागर किया। इन चुनावी परिणामों से परे, ये उपचुनाव भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किए गए सक्रिय उपायों के लिए भी उल्लेखनीय रहे, हालांकि बूथ-स्तर की पारदर्शिता और हिंसा को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।

मुख्य राजनीतिक झलकियाँ:

1. **केरल (नीलांबूर):**
   - o कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ ने जीत हासिल की।
   - o यह सीट वायनाड लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जो प्रियंका गांधी के पास है।
   - o भाजपा का प्रदर्शन कमजोर रहा।
   - o यह 2026 के केरल विधानसभा चुनावों से पहले गठबंधन समीकरणों और प्रचार रणनीतियों को प्रभावित कर सकता है।
2. **पश्चिम बंगाल (कालिगंज):**
   - o टीएमसी की अलीफा अहमद ने भारी अंतर से जीत दर्ज की।
   - o चुनाव के दौरान हिंसा हुई — एक बच्चे की कच्चे बम विस्फोट में मौत हो गई, जिससे कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता उत्पन्न हुई।
   - o यह राज्य में चुनावी हिंसा की प्रवृत्ति को दर्शाता है।
3. **गुजरात (कड़ी – एससी) और विसावदर:**
   - o भाजपा ने कड़ी सीट बरकरार रखी।
   - o आम आदमी पार्टी ने विसावदर सीट पुनः हासिल की, जो दिल्ली की हार के बाद गुजरात की राजनीति में उसकी दृढ़ता को दर्शाता है।
4. **पंजाब (लुधियाना पश्चिम):**
   - o आप के संजीव अरोड़ा ने जीत हासिल की, जिससे पार्टी ने उस राज्य में अपनी उपस्थिति बनाए रखी जहां वह सत्ता में है।

चुनावी प्रक्रिया और ECI के सुधार:

भारत निर्वाचन आयोग ने पहुँच, पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए कई सुधार लागू किए:

Polls and processes

The ECI is taking some proactive steps towards transparency

The results of the by-elections in five Assembly constituencies – Kadi (SC) and Visavadar in Gujarat, Nilambur in Kerala, Ludhiana West in Punjab and Kaliganj in West Bengal – indicate the factors at play at the local and regional levels. The Congress-led United Democratic Front candidate Aryadan Shoukath won the Nilambur seat. P.V. Anvar, who had won in 2021 as a Left-backed independent, vacated the seat after a spat with the ruling coalition, contested as a Trinamool Congress (TMC) candidate (which was rejected) and then stood as an independent. The seat falls in the Wayanad Lok Sabha constituency represented by Congress leader Priyanka Gandhi. The Bharatiya Janata Party (BJP) candidate performed poorly. The outcome could impact the tone of the campaigning for the Kerala Assembly elections due next year. The alignment of communities and relative power of parties in both Fronts will be affected by the Nilambur result. In the Kaliganj constituency in Nadia district, the ruling TMC's candidate Alifa Ahmed won by a margin of over 50,000 votes. Her father's death had led to the by-poll. Counting day was marred by the death of a child in a crude bomb explosion, a sign of the continuing and disturbing role of violence in the State. Assembly elections in West Bengal will take place next year.

The Aam Aadmi Party (AAP)'s wins in Visavadar and Ludhiana West are significant for a party that lost power in Delhi, its original stronghold, in February. Its MLA in Visavadar had defected to the BJP, and the renewed mandate helps AAP retain its stake in State politics. Its former State president Gopal Italia is the winner. AAP's former Rajya Sabha Member of Parliament and industrialist Sanjeev Arora won the Ludhiana West seat in a State it rules. The BJP retained Kadi. The by-polls were also notable for the new initiatives by the Election Commission of India (ECI) to reinforce the integrity of the electoral process and make it more accessible. These include mobile deposit facility for the electors at all polling stations, upgraded voter turnout sharing process resulting in faster updating of the approximate polling trends, and most significantly, webcasting at 100% of polling stations. The issues of disputes over heavy polling in sensitive booths in the concluding hours of voting and transparency related to video records of booth activities remain, and the ECI must continue to take proactive measures to not only be fair but also to be seen so.

- सभी मतदान केंद्रों पर मोबाइल जमा सुविधाएँ।
- वास्तविक समय की निगरानी के लिए मतदान प्रतिशत डेटा का त्वरित साझाकरण।
- सभी मतदान बूथों से 100% वेबकास्टिंग, जिससे कदाचार की संभावना कम हो और पारदर्शिता बढ़े।

हालांकि, कुछ चिंताएं बनी हुई हैं:
- संवेदनशील बूथों में असमान रूप से अधिक मतदान, विशेषकर अंतिम घंटों में।
- वेबकास्ट से प्राप्त वीडियो रिकॉर्ड की पहुंच और सत्यापन की प्रक्रिया को लेकर अस्पष्टता।
- पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही चुनावी हिंसा, जिससे मतदाता विश्वास और लोकतांत्रिक मानदंडों पर असर पड़ता है।

व्यापक प्रभाव:

1. **संघीय राजनीतिक गतिशीलता:**
   - o विभिन्न राज्यों से मिले परिणाम विभाजित राजनीतिक पसंद और स्थानीय मुद्दों के महत्व को दर्शाते हैं।
   - o आप का मिश्रित प्रदर्शन यह दिखाता है कि दिल्ली और पंजाब से बाहर प्रभाव बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है।
2. **चुनावी संस्थाओं की भूमिका:**
   - o निर्वाचन आयोग की तकनीकी और प्रशासनिक नवाचार इसकी लोकतंत्र को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
   - o हालांकि, चुनावी ईमानदारी में विश्वास केवल प्रणालियों पर नहीं, बल्कि स्पष्ट निष्पक्षता और सख्त प्रवर्तन पर भी निर्भर करता है।
3. **चुनावी सुधारों की आवश्यकता:**
   - o बूथ-स्तर की पारदर्शिता को मजबूत करना, वीडियो रिकॉर्ड ऑडिट सुनिश्चित करना, और चुनावी हिंसा को संबोधित करना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए आवश्यक है।
   - o निर्वाचन आयोग की निष्पक्ष संस्था के रूप में विश्वसनीयता को निरंतर और समयबद्ध कार्रवाई से मजबूत करना होगा।

निष्कर्ष:
उपचुनावों के परिणाम क्षेत्रीय राजनीतिक हलचल और बदलती मतदाता प्राथमिकताओं का मिश्रण दर्शाते हैं। जहां निर्वाचन आयोग की तकनीक के उपयोग और मतदाता सुविधा सुधारों की पहल सराहनीय है, वहीं बूथ-स्तर की अनियमितताओं और चुनाव के समय हिंसा को लेकर बनी चिंताएँ गहरे सुधारों की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। यह सुनिश्चित करना कि चुनाव प्रक्रिया न केवल निष्पक्ष हो बल्कि स्पष्ट रूप से निष्पक्ष दिखाई दे, भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बुनियादी चुनौती बनी हुई है।

UPSC Mains Practice Question

Ques : "चुनाव का मतलब केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष होना ही नहीं है, बल्कि ऐसा दिखना भी है।" हाल के उपचुनावों और चुनाव आयोग के सुधारों के मद्देनजर, भारत में चुनावी पारदर्शिता सुनिश्चित करने में चुनौतियों और प्रगति की आलोचनात्मक जांच करें। **(250 Words)**

Page : 09 : GS 3 : Indian Economy

भारत ने मई 2025 में मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की (2.8%), जो भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के लक्षित दायरे के भीतर है। हालांकि, यह उस समय हुआ जब बेरोजगारी दर बढ़कर 5.8% हो गई और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर पिछले वर्ष के 9.2% से घटकर 6.5% रह गई। इन प्रमुख मैक्रोइकॉनॉमिक संकेतकों के बीच असंगति ने मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता, मुद्रास्फीति के वास्तविक कारणों और भारत की संरचनात्मक आर्थिक समस्याओं पर बहस को फिर से शुरू कर दिया है।

Inflation falls but not unemployment

Pulapre Balakrishnan

is a Honorary Visiting Professor at the Centre for Development Studies, Thiruvananthapuram

M. Parameswaran

is Professor at the Centre for Development Studies, Thiruvananthapuram

At less than 3%, the inflation figure for May is well within the target set by the government of India. This has led to a celebration in the media of the Reserve Bank of India's prowess in macroeconomic management. What has received next to no acknowledgement, though, is that in the same month, unemployment had risen. Thus, while year-on-year inflation fell from 3.2% in April to 2.8% in May, the latest Periodic Labour Force Survey shows that the unemployment rate rose from 5.1% in April to 5.8% in May.

For those employed, as most commentators on the economy are likely to be, a reduction in inflation is good news, to the extent that their purchasing power is being eroded at a lower rate. But for those seeking employment, it makes no difference. They remain unemployed. A branch of economic theory dominant in the U.S. asserts that the unemployed have chosen not to work, as the market mechanism enables everyone who wishes to work to find employment. One needs only to visit the town centre in semi-urban areas to find migrant labourers milling around at midday to conclude that this would be a preposterous claim to make for India.

So, the first thing to note is that to monitor inflation while neglecting unemployment, as the pundits do, is not a credible way of assessing the state of an economy. While missing the higher unemployment rate in May may be overlooked, as it is not part of the discourse on India's economy today, it is surprising that the considerable reduction in growth has not received as much attention, when growth has been the centrepiece of the government's pronouncements on the economy this past decade. The figures are as follows. GDP growth slid from 9.2% during 2023-24 to 6.5% in 2024-25. The observed rise in unemployment is consistent with this decline in growth.

Monitoring inflation while ignoring unemployment is not a credible way of assessing economic performance

The provisional estimates of GDP show the decline in growth to be spread across three quarters of the economy. Apart from Public Administration, for which the growth rate held, every other sector slowed in 2024-25. Agriculture alone grew faster, and much faster too. This development provides the clue to the decline in inflation. In 2024-25, the relative rates of growth of the agricultural and non-agricultural sectors would have led to a reduction of the supply-demand gap for agricultural goods, particularly food, in turn contributing to a lowering of the inflation rate. This is evident in the sharp deceleration in food-price inflation from the peak of close to 11% in October 2024 to less than 1% in May 2025.

Monetary policy, which is the RBI's means for inflation control, could not have achieved the observed configuration of events. It would be difficult to maintain that an increase in the repo rate of just over 10% in June 2022, which has not been exceeded since, could have triggered so great a reduction in food inflation from late 2024. It is equally difficult to imagine that it could have brought about so widespread a slowing of the economy in 2024-25, especially of services, a large segment of which is unlikely to be dependent upon formal credit. On the other hand, the impact of a narrowing difference in the rates of growth of the agricultural and non-agricultural sectors of the economy, as witnessed, can have a direct impact on the inflation rate. The reduction in food-price inflation impacts inflation directly, as food prices are part of the consumer price index, and indirectly via rising wages, which feed into the price of non-agricultural goods.

Econometric evidence

We have so far evaluated the role of monetary policy in relation to events. The economics profession usually settles empirical issues via econometrics–the application of statistical methods to economic models. This leaves little in doubt as to the inefficacy of monetary policy for inflation management. In our article "Inflation in India: Dynamics, distributional impact and policy implication" ('Structural change and Economic Dynamics', June 2025), we demonstrate that there is no conclusive evidence of the role of the interest rate in controlling inflation in India.

On the other hand, there is conclusive econometric evidence of the overwhelming role of the price of agricultural goods, driven by the relative rates of growth of the agricultural and non-agricultural sectors. Inflationary pressure generated by such a mechanism requires augmenting supply to be controlled. Inflation targeting, which works via contraction of demand, is not a solution. If, in the face of a persistent excess demand for agricultural goods, inflation is lowered by hiking the interest rate in order to restrain demand, other things remaining the same, inflation will rise when next the interest rate is lowered and growth revives.

Two final observations should seal the debate on RBI's role in lowering inflation rate. First, an allegedly sophisticated view of RBI's 'inflation targeting' holds that a central bank can control inflation by influencing expectations of economic agents. When we study the RBI's own data on the expectation of inflation by households, we find that it has remained almost unchanged from March 2024 to May 2025, and has been far higher than the RBI's target of 4%. Hence, the recent decline could not have been engineered by inflation targeting.

Secondly, after the last Monetary Policy Committee meeting, RBI Governor expressed willingness to lower repo rate again if inflation continues to decline. Such a stance would imply that India's monetary policy merely follows inflation rather than directing its course.

मुख्य मुद्दे:

1. **मुद्रास्फीति बनाम बेरोजगारी का असंतुलन:**
   o गिरती मुद्रास्फीति उपभोक्ताओं को लाभ देती है क्योंकि इससे उनकी क्रय शक्ति का क्षरण धीमा होता है, लेकिन बेरोजगारी की चिंता बनी रहती है, विशेषकर नौकरी तलाशने वालों के लिए।

o भारत का श्रम बाजार पूर्ण रोजगार की धारणा को नहीं दर्शाता, जैसा कि विकसित देशों में होता है; यहाँ बड़े पैमाने पर असंगठित और अल्प-रोजगार वाले वर्ग मौजूद हैं।

2. **धीमी होती आर्थिक वृद्धि:**
   o 2024–25 में GDP वृद्धि में तेज गिरावट देखी गई।
   o यह मंदी व्यापक थी, जो कृषि और सार्वजनिक प्रशासन को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों को प्रभावित कर रही थी।
   o बेरोजगारी में वृद्धि धीमी होती अर्थव्यवस्था के अनुरूप है, जो संरचनात्मक मांग संबंधी समस्याओं की ओर इशारा करती है।
3. **कृषि-आधारित मुद्रास्फीति में कमी:**
   o कृषि में गैर-कृषि की तुलना में तेज़ी से हुई वृद्धि ने खाद्य वस्तुओं में आपूर्ति और मांग के बीच की खाई को कम कर दिया, जिससे खाद्य मुद्रास्फीति अक्टूबर 2024 के 11% से घटकर मई 2025 में 1% से नीचे आ गई।
   o यह संरचनात्मक पुनर्संतुलन — न कि रेपो दर समायोजन — मुद्रास्फीति में नरमी के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार था।
4. **मौद्रिक नीति की सीमाएँ:**
   o RBI ने जून 2022 में रेपो दर में 1% से अधिक की वृद्धि की, लेकिन तब से इसे स्थिर रखा है।
   o सेवा क्षेत्र, जो GDP का बड़ा हिस्सा है, औपचारिक ऋण के प्रति कम संवेदनशील है; इसलिए रेपो दर परिवर्तनों का सीमित प्रभाव है।
   o अनुभवजन्य अध्ययनों (जैसे कि *Structural Change and Economic Dynamics* में उद्धृत शोधपत्र) में भारत में ब्याज दर परिवर्तनों और मुद्रास्फीति के बीच कमजोर संबंध पाए गए हैं।
5. **मुद्रास्फीति की अपेक्षाएँ और नीति की विश्वसनीयता:**
   o घरेलू मुद्रास्फीति अपेक्षाएँ लगातार 4% के लक्ष्य से ऊपर बनी रहीं, जो यह दर्शाता है कि RBI की नीतियों का जनमानस पर सीमित प्रभाव है।
   o RBI द्वारा रेपो दर में कटौती केवल मुद्रास्फीति के घटने के बाद करने की प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि वह रुझानों के अनुसार प्रतिक्रिया करता है, बजाय इसके कि वह उन्हें proactively नियंत्रित करे।

व्यापक प्रभाव:

1. **मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण पर पुनर्विचार:**
   o भारत की मुद्रास्फीति आपूर्ति-आधारित है, विशेष रूप से खाद्य कीमतों में।
   o जब मुद्रास्फीति आपूर्ति बाधाओं के कारण हो, तब रेपो दर में वृद्धि जैसी पारंपरिक मुद्रास्फीति नियंत्रण नीतियाँ अप्रभावी होती हैं।
   o एक उत्पादन-उन्मुख दृष्टिकोण — जो कृषि और अवसंरचना में आपूर्ति बढ़ाने पर केंद्रित हो — अधिक उपयुक्त हो सकता है।
2. **रोजगार-केंद्रित मैक्रोइकॉनॉमिक नीति:**
   o बेरोजगारी की उपेक्षा नागरिकों की समग्र भलाई और वृद्धि की स्थिरता को कमजोर करती है।
   o भारत को मुद्रास्फीति नियंत्रण और रोजगार सृजन — दोनों पर समान रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसके लिए संभवतः राजकोषीय समर्थन, कौशल विकास और लक्षित रोजगार कार्यक्रमों की ज़रूरत होगी।
3. **बेहतर मापन और विमर्श की आवश्यकता:**
   o सार्वजनिक और नीतिगत ध्यान अक्सर केवल मुद्रास्फीति की ओर केंद्रित रहता है, जबकि बेरोजगारी, अल्प-रोजगारी और असंगठित क्षेत्र की पीड़ा जैसे समान रूप से महत्वपूर्ण संकेतकों की उपेक्षा होती है।
   o एक समग्र मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो केवल शीर्षक मुद्रास्फीति (headline inflation) से संचालित न हो।

निष्कर्ष:
मई 2025 में मुद्रास्फीति में तेज गिरावट को बेरोजगारी में चिंताजनक वृद्धि और धीमी आर्थिक वृद्धि की अनदेखी कर नहीं देखा जाना चाहिए। वर्तमान आंकड़े रोजगार सृजन की संरचनात्मक समस्याओं और मुद्रास्फीति के भारतीय परिदृश्य में मौद्रिक नीति की सीमित प्रभावशीलता को उजागर करते हैं। यह आवश्यक है कि आर्थिक नीति केवल रेपो दर और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) तक सीमित न रहे, बल्कि वास्तविक अर्थव्यवस्था की चुनौतियों — जैसे बेरोजगारी और क्षेत्रीय असंतुलन — को प्राथमिकता दे। केवल तभी मैक्रोइकॉनॉमिक प्रबंधन को वास्तव में सफल माना जा सकता है।

UPSC Mains Practice Question

Ques: "यदि बेरोजगारी बढ़ती रहती है तो मुद्रास्फीति में गिरावट आवश्यक रूप से आर्थिक स्वास्थ्य का संकेत नहीं है।" भारत में हाल के आर्थिक रुझानों के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण करें। **(250 words)**

Page : 08 Editorial Analysis

The sorry state of South Asian economic integration

Shashank Patel

is a scholar of international trade law at the South Asian University (SAU), New Delhi

In the year so far there were two major incidents that shook India's economic and national security landscape: the reciprocal tariffs imposed by the Trump administration and the terror attack in Pahalgam. While these events may seem unrelated, their underlying causes and consequences are deeply interlinked, highlighting the urgent need for a comprehensive regional approach to security and economic stability. Economic and national security are often discussed separately, but they are deeply intertwined.

Border disputes among South Asian nations significantly hamper trade and economic cooperation, preventing the region from achieving its full potential. Economic instability fuels unrest, while security threats disrupt trade and investment. No country can achieve lasting security without economic prosperity, and vice versa.

One of the least integrated

The South Asian region is one of the least economically integrated regions in the world. Intraregional trade of South Asia (South Asian Free Trade Area or SAFTA) accounts for barely 5% to 7% of its total international trade, which is the lowest when compared to other trading blocs. In contrast, intraregional trade accounts for approximately 45% of total international trade within the European Union (EU), 22% within the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), and around 25% within North American Free Trade Agreement (NAFTA).

Current trade among South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) countries is just around $23 billion, far below the estimated $67 billion. According to a United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) study, South Asia's potential trade could have reached $172 billion by 2020, which means over 86% of its capacity remains unexploited. Even if we consider this assessment to be optimistic, the immense potential for significantly increasing intra-SAARC trade can never be denied. South Asia, the most populous region of the world (25% of the world's population), represents a combined market of only $5 trillion in GDP. On the other side, the EU, with 5.8% of the world's population, accounts for $18 trillion in GDP, and NAFTA has a GDP of $24.8 trillion. This clearly shows the underexploited capacity of the South Asian region.

Trust deficits and regional conflicts are hindering the full implementation of key trade agreements

There is much potential

As estimated by the UNESCAP South Asia Gravity Model of intraregional trade, in spite of trade liberalisation under SAFTA, intraregional trade in South Asia is less than a third of its potential. Bangladesh has the highest unexploited proportion, at 93%, followed by the Maldives (88%), Pakistan (86%), Afghanistan (83%), and Nepal (76%). Because of terror insurgencies and border disputes, trade between India and Pakistan has seen a significant decline over the years. Bilateral trade between India and Pakistan fell from $2.41 billion in 2018 to $1.2 billion in 2024. Further, Pakistani exports to India fell from $547.5 million in 2019 to just $480,000 in 2024.

South Asia's trade-to-GDP ratio decreased from 47.30% in 2022 to 42.94% in 2024. Additionally, the World Bank reported a softened growth forecast of 5.8% for 2025, down from 6% in 2024. As imports have grown faster than exports for all South Asian countries, the trade deficit of the subregion has widened from $204.1 billion in 2015 to $339 billion in 2022. However, the value of overall trade, covering both exports and imports, increased significantly between 2015-22 to approximately $1,335 billion.

Despite SAFTA, trading with neighbours is not 'free'. The inefficient trade governing mechanism and an unpromising political environment increase the cost of intraregional trade, which is one of the major reasons for significantly smaller intra-regional trade. Costs of trading within South Asia remain high at 114% of the value of the goods being exported, making trading with neighbouring nations more expensive or less competitive, compared to trading with distant partners.

For instance, South Asia's bilateral trade cost with the U.S. is only 109% despite the vastly greater distance. It is about 20% more costly for a company in India to trade with Pakistan than with Brazil, which is 22 times farther away. This discourages the formation of regional value chains despite the geographic contiguity. In contrast, intraregional trade costs for ASEAN are some 40% lower than intra-SAARC trade costs, at 76%, creating high incentives for interdependence in that bloc.

The main hurdles

The low level of intraregional trade in South Asia demonstrates the absence of strategic policies. SAFTA and other regional agreements have the potential to create greater economic linkages. Besides, over two-thirds of the potential of intraregional trade in goods, the potential of trade in services, and investments in South Asia remain untapped. To this end, greater regional cooperation could facilitate the development of complementary and mutually beneficial export sectors by focusing on lowering trade barriers.

SAARC had the aim of ending distrust and tension, but trust deficits and regional conflicts hinder the full implementation of agreements such as SAFTA. Political diversity, regional disputes, minority issues and terrorism are major obstacles to regional cooperation. Most SAARC countries are in conflict with each other, preventing effective regional integration. Lesser trade opportunity means lesser capacity for innovation, production and investment in the people of the country. Therefore, to exploit the full potential of the South Asian region, members must work actively to enhance intra-regional trade, keeping aside their bilateral conflicts.

Paper 02 : Internaional Relations

UPSC Mains Practice Question : "सार्क की विफलता दक्षिण एशिया में भू-अर्थशास्त्र पर भू-राजनीति के प्रभुत्व को दर्शाती है।" क्षेत्र के कम अंतर-क्षेत्रीय व्यापार के संदर्भ में इस कथन की आलोचनात्मक जांच करें। (250 words)

Context :

हालांकि दक्षिण एशिया विश्व की 25% जनसंख्या का घर है, फिर भी यह विश्व के सबसे कम आर्थिक रूप से एकीकृत क्षेत्रों में से एक बना हुआ है। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA) के तहत अंतर-क्षेत्रीय व्यापार कुल व्यापार का मात्र 5–7% है, जो यूरोपीय संघ (EU), आसियान (ASEAN), और नैफ्टा (NAFTA) जैसे अन्य क्षेत्रीय ब्लॉकों के मुकाबले बेहद कम है। भारत–पाकिस्तान व्यापार में हालिया गिरावट, बढ़ते व्यापार घाटे, और अपूर्ण व्यापार संभावनाएं SAARC-प्रेरित क्षेत्रीयता की विफलता और राजनीतिक व आर्थिक पुनर्समर्पण की आवश्यकता को उजागर करती हैं।

प्रमुख आँकड़े:

- **SAARC के भीतर व्यापार:** $23 बिलियन (संभावित व्यापार $67–$172 बिलियन के मुकाबले)।
- **दक्षिण एशिया का व्यापार-से-GDP अनुपात:** 47.3% (2022) से घटकर 42.94% (2024)।
- **SAARC क्षेत्र के भीतर व्यापार लागत:** निर्यात मूल्य का 114% (अमेरिका के साथ व्यापार लागत से भी अधिक)।
- **भारत–पाकिस्तान व्यापार:** $2.41 बिलियन (2018) से घटकर $1.2 बिलियन (2024)।
- **SAARC की संयुक्त GDP:** ~$5 ट्रिलियन (EU: $18 ट्रिलियन; NAFTA: $24.8 ट्रिलियन)।

मुख्य समस्याएँ:

1. **सुरक्षा–अर्थव्यवस्था संबंध:**
   - o लगातार सीमा संघर्ष, आतंकवाद और पारस्परिक अविश्वास व्यापार संबंधों को सीधे प्रभावित करते हैं।
   - o भारत और पाकिस्तान के बीच विशेष रूप से, राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएँ क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग पर हावी हो जाती हैं।

2. **उच्च व्यापार लागत:**
   - o SAARC के भीतर व्यापार, अमेरिका और ब्राज़ील जैसे दूरस्थ देशों के साथ व्यापार की तुलना में अधिक महंगा है।
   - o कमजोर लॉजिस्टिक्स, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, गैर-शुल्क बाधाएं, और जटिल सीमा प्रक्रियाएं लागत को बढ़ाती हैं।

3. **संस्थागत अक्षमता:**
   - o SAFTA का सीमित क्रियान्वयन, सदस्य देशों के बीच विश्वास की कमी को दर्शाता है।
   - o SAARC की कमजोर संस्थागत संरचना, दुर्लभ शिखर सम्मेलन, और प्रवर्तन तंत्र की कमी एकीकरण को बाधित करती है।

4. **राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी:**
   - o राजनीतिक तनाव, अल्पसंख्यक मुद्दे, और आपसी संदेह व्यापार सुगमता पर सहमति को बाधित करते हैं।
   - o घरेलू राजनीति अक्सर क्षेत्रीय कूटनीति में बाधा डालती है।

5. **अपूर्ण व्यापार संभावनाएं:**
   - o सेवाओं और निवेश का व्यापार काफी हद तक अनछुआ है।
   - o क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाएं (regional value chains) अविश्वास, बुनियादी ढांचे की कमी, और समन्वित नीतियों के अभाव में विकसित नहीं हो सकी हैं।

तुलनात्मक दृष्टिकोण:

- ASEAN और EU की सफलता के कारण:
  - o मजबूत संस्थागत ढांचे।
  - o रणनीतिक नीतिगत समन्वय।

o राजनीति से पृथक आर्थिक सहयोग।
o कम व्यापार लागत (~76% ASEAN में)।
दक्षिण एशिया, भौगोलिक निकटता के बावजूद, परस्पर निर्भरता से वंचित है, जो सतत एकीकरण के लिए आवश्यक है।

व्यापक प्रभाव:

1. **विकास के अवसरों का नुकसान:**
   o सीमित क्षेत्रीय व्यापार नवाचार, उत्पादन विस्तार, रोजगार और गरीबी उन्मूलन के अवसरों को सीमित करता है।

2. **रणनीतिक असुरक्षा:**
   o आंतरिक क्षेत्रीय एकीकरण की कमी देशों को बाहरी शक्तियों पर अधिक निर्भर बनाती है, जिससे रणनीतिक स्वायत्तता प्रभावित होती है।

3. **जनता-से-जनता संपर्क में कमी:**
   o व्यापार और आवाजाही में कमी सांस्कृतिक अलगाव को जन्म देती है और जनस्तर पर विश्वास निर्माण को बाधित करती है।

आगे की राह:
• **SAFTA में सेवाएं, निवेश और डिजिटल व्यापार को शामिल करने हेतु सुधार।**
• **राजनीति से व्यापार को अलग करना:** राजनीतिक मतभेदों के बावजूद आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करना।
• **सीमा-पार बुनियादी ढांचे में निवेश:** सड़कें, रेल, सीमा शुल्क का सामंजस्य।
• **क्षेत्रीय गठबंधन बनाना:** जैसे कि ऊर्जा ग्रिड, पर्यटन सर्किट, कृषि बाजार।
• **SAARC के असफल होने पर BIMSTEC जैसे संस्थानों को मजबूत करना, साथ ही SAARC संवाद को जीवित रखना।**

निष्कर्ष:
दक्षिण एशिया का आर्थिक रूप से अल्प-एकीकृत होना राजनीतिक असमानता का कारण और परिणाम दोनों है। क्षेत्र में जनसंख्या, बाजार आकार और साझा सांस्कृतिक-ऐतिहासिक जुड़ाव जैसी अपार संभावनाएँ होते हुए भी, यह प्रदर्शन करने में पिछड़ता रहा है। विश्वास निर्माण, संस्थागत सुदृढ़ीकरण और राजनीति से व्यापार को अलग करने पर केंद्रित रणनीतिक पुनर्संयोजन दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय संभावनाओं को unlock करने के लिए आवश्यक है।